पंजाब केसरी

Tue, 23 May, 2017

रक्षा प्रणाली देगा इस्राइल

येरूशलम, (भाषा): इस्राइल की सरकारी इस्राइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज (आईएआई) ने कहा है कि भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ संयुक्त रूप से किए गए 63 करोड़ डॉलर के समझौते के तहत इस्राइल भारतीय नौसेना के चार पोतों के लिए लंबी दूरी की आधुनिक वायु और मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करेगा। समझौते की घोषणा ऐसे समय की गई है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुलाई माह में संभवत: इस्राइल के दौरे पर जा सकते हैं।

रक्षा समझौता

- हवाई, सामुद्रिक और वायुजनित खतरों के लिए मजबूत कवच सिद्ध होगी यह रक्षा प्रणाली

इस्राइल ने पिछले महीने अपना अब तक का सबसे बड़ा दो अरब डॉलर का सौदा किया था जिसके तहत वह भारतीय सेना और नौसेना को मिसाइल रक्षा प्रणाली की आपूर्ति करेगा। इस सौदे में 1.6 अरब डॉलर का सबसे बड़ा हिस्सा आईएआई का है। आईएआई ने कहा कि हाल का सौदा लांग रेंज सर्फेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स (एलआरएसएएम) की आपूर्ति से जुड़ा है। एलआरएसएएम का निर्माण आईएआई और भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने संयुक्त रूप से किया है। यह प्रणाली विभिन्न तरह के हवाई, सामुद्रिक तथा वायुजनित खतरों से मजबूत संरक्षण देती है। भारतीय सेना भी जल्द ही इसकी तैनाती कर सकती है। आईएआई की ओर से जारी वक्तव्य में बताया गया कि पिछले हफ्ते एलआरएसएएम का भारत में नौसेना के पोत पर सफल परीक्षण किया गया। यह इस किस्म का पहला ऐसा करार है जिसमें भारत सरकार के स्वामित्व वाला बीईएल मेक इन इंडिया नीति के तहत परियोजना का मुख्य ठेकेदार होगा। आईएआई के अध्यक्ष एवं सीईओ जोसफ वेईस ने कहा कि इस नए समझौते के अलावा बीते एक दशक में आईएआई ने भारत के रक्षा बलों के साथ कई अन्य समझौते भी किए हैं जो वायु एवं मिसाइल रक्षा प्रणाली के क्षेत्र में आईएआई के वैश्विक नेतृत्व की स्थिति को और मजबूती देते हैं। भारत सरकार की कंपनी बीईएल को पहली बार शामिल करना 'मेक इन इंडिया' नीति के तहत भारतीय उद्योग के साथ हमारे संबंधों की दिशा में बढ़ाया गया कदम है। उन्होंने कहा कि यह अनूठी परियोजना भारत के डीआरडीओ, आईएआई और दोनों देशों के रक्षा बलों के बीच नजदीकी संबंधों को रेखांकित करती है। हम इसे संयुक्त प्रयासों के जरिए क्रियान्वित करने की दिशा में बढ़ेंगे।

अटल मिशन के तहत 78 करोड़ रुपये की डीपीआर मंजूर

नई दिल्ली, (वार्ता): जम्मू-कश्मीर के लिए अटल मिशन के तहत 78 करोड़ रुपये की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट(डीपीआर) को मंजूरी दी गयी है। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने आज यहां ट्वीट करके यह जानकारी दी। जम्मू-कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के अलावा अनंतनाग,लेह और कारगिल को अटल मिशन के तहत विकसित किया जाना है।

अटल मिशन के तहत वर्ष 2015 से 2020 तक 593. 05 करोड़ रुपये की लागत से इन शहरों की जलापूर्ति और जलनिकासी,परिवहन प्रणाली में सुधार के अलावा पार्क आदि विकसित किये जाने हैं।